www.sanjanabharati.com
दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित
facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक
संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

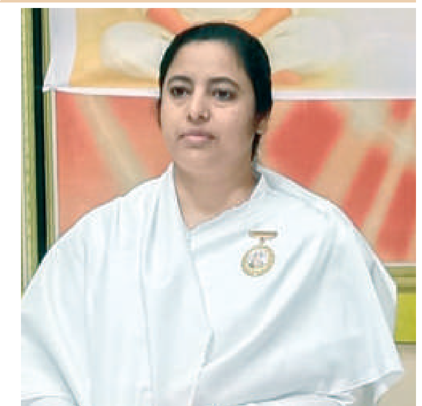

2 विधेयक पर हंगामा क्यों, जब मुद्दा है...
3 श्री खाटू श्याम मंदिर में धूमधाम से मनाई गई भगवान...
4 दादी प्रकाशमणि की स्मृति में 23 को होगा...

वर्ष: 9 | अंक: 298 | दिल्ली, शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

सतीश गोलचा होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर

नई दिल्ली (एजेन्सी)। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने इसको लेकर जानकारी दी है। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा वर्तमान में दिल्ली में महानिदेशक (कारागार) के पद पर तैनात हैं। गृह मंत्रालय द्वारा 21 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, सतीश गोलचा, आईपीएस (एजीएमयूटी:1992), जो वर्तमान में दिल्ली के महानिदेशक (कारागार) के पद पर तैनात हैं, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक दिल्ली के पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त किया जाता है। गोलचा, होमगाड्र्स के महानिदेशक एसबीके सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त को दिल्ली पुलिस का कार्यवाहक आयुक्त नियुक्त किया था। यह घटनाक्रम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सिविल लाइंस स्थित उनके आधिकारिक आवास पर आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के एक दिन बाद हुआ है। गुप्ता पर गुजरात के राजकोट से आए एक 41 वर्षीय व्यक्ति ने हमला किया, जो शिकायतकर्ता बनकर अंदर घुसा था। राजकोट निवासी ऑटो चालक, आरोपी राजेशभाई खिमजीभाई सकरिया को मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम और वहाँ मौजूद अन्य लोगों ने पकड़ लिया। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

संविधान संशोधन विधेयक लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम, पुनर्विचार करे सरकार: मायावती

उत्तर प्रदेश (एजेन्सी)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने बृहस्पतिवार को 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम करार देते हुए केन्द्र सरकार से इसपर पुनर्विचार का आग्रह किया। मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, केन्द्र सरकार द्वारा कल (बुधवार को) संसद में, भारी हंगामे के बीच लाया गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक देश में पिछले कुछ वर्षों से जारी राजनैतिक हालात में यह स्पष्टतः लोकतंत्र को कमजोर करने वाला लगता है और सत्ताधारी पार्टियां अपने-अपने लाभ, स्वार्थ व द्वेष में ज्यादातर इसका दुरुपयोग ही करेंगी, ऐसी जनता को आशंका है। उन्होंने कहा, अतः इस विधेयक से हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। सरकार देश के लोकतंत्र एवं संविधान के हित में इसपर जरूर पुनर्विचार करे। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 में प्रधानमंत्री, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर अपराध के आरोपों में पद से हटाने का प्रावधान है। इस विधेयक का विपक्षी सदस्यों ने तीखा विरोध किया और प्रस्तावित कानून को संविधान व संघवाद की भावना के विरुद्ध बताया।

तीर्थयात्रियों की बस खाई में गिरी, एक की मौत

जम्मू-कश्मीर (एजेन्सी)। जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में बृहस्पतिवार को माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर जा रहे तीर्थयात्रियों की बस जम्मू-पठानकोट राजमार्ग से फिसलकर खाई में गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 39 लोग घायल हो गये। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना जटवाल में हुई जब उत्तर प्रदेश से कटरा जा रहे तीर्थयात्रियों की बस का टायर फट गया और वह एक छोटे पुल के पास राजमार्ग से फिसल गई। उन्होंने कहा कि मृतक की पहचान अमरोहा निवासी 45 वर्षीय इकबाल सिंह के रूप में हुई है। दुर्घटना के बाद एक बचाव अभियान शुरू किया गया और घायलों को सांबा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उनमें से सात लोगों को बाद में विजयपुर स्थित एम्स अस्पताल में स्थानांतरित किया गया।

मुख्यमंत्री ने 'हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग' की स्थापना की घोषणा की

एसबी संवाददाता/चंडीगढ़। राज्य में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करने हेतु 'हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग' की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार हरियाणा को देश का नंबर एक स्टार्टअप हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य राज्य में स्टार्टअप्स की संख्या को तीन गुना करना है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में 'विश्व उद्यमिता दिवस' के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह और कई अन्य घोषणाएँ कीं। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रणबीर गंगवा और युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता मंत्री श्री गौरव गौतम भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में राज्य भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 2,000 विद्यार्थियों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 100 सफल उद्यमियों ने भाग लिया।

भारतीय रेल चलाएगी रिकॉर्ड 380 गणपति स्पेशल ट्रेन यात्राएँ

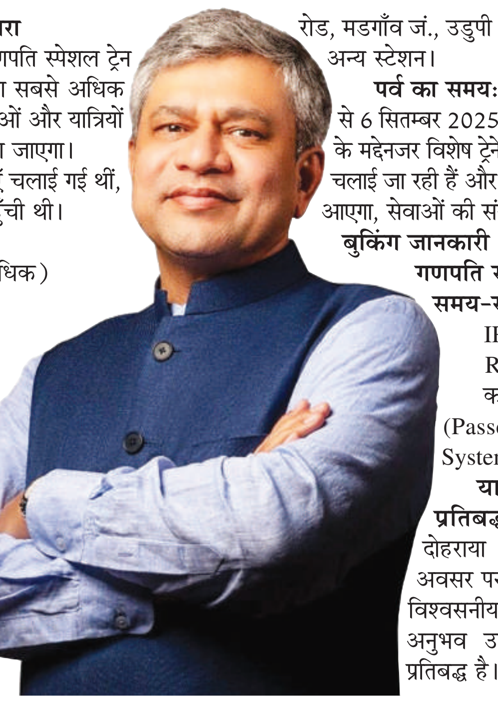

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

गोरखपुर। भारतीय रेल ने इस वर्ष 380 गणपति स्पेशल ट्रेन यात्राओं की घोषणा की है, जो अब तक का सबसे अधिक आँकड़ा है। इन विशेष ट्रेनों से लाखों श्रद्धालुओं और यात्रियों की यात्रा को सुगम और आरामदायक बनाया जाएगा।

2023 में कुल 305 स्पेशल ट्रेन यात्राएँ चलाई गई थीं, जबकि 2024 में यह संख्या 358 तक पहुँची थी।

जोनवार विवरण:

सेंट्रल रेलवे: 296 यात्राएँ (सबसे अधिक)

वेस्टर्न रेलवे: 56 यात्राएँ

कोंकण रेलवे (KRCL): 6 यात्राएँ

साउथ वेस्टर्न रेलवे: 22 यात्राएँ

महाराष्ट्र और कोंकण के लिए विशेष सेवाएँ

इन ट्रेनों का सबसे अधिक लाभ महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र के यात्रियों को मिलेगा, जहाँ गणपति पूजा के दौरान सबसे अधिक भीड़ होती है। कोंकण रेलवे मार्ग पर रुकने वाले प्रमुख स्टेशन होंगे झ कोलाड, चिपलून, रत्नागिरी, कणकवली, सावंतवाड़ी रोड, मडगाँव जं., उडुपी और सूरथकल सहित कई अन्य स्टेशन।

पर्व का समय: गणपति पूजा 27 अगस्त से 6 सितम्बर 2025 तक मनाई जाएगी। त्योहार के मद्देनजर विशेष ट्रेनें 11 अगस्त 2025 से ही चलाई जा रही हैं और जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आएगा, सेवाओं की संख्या और बढ़ाई जाएगी।

बुकिंग जानकारी

गणपति स्पेशल ट्रेनों की विस्तृत समय-सारणी उपलब्ध है-

IRCTC वेबसाइट पर

RailOne ऐप पर

कम्प्यूटरीकृत पीआरएस (Passenger Reservation System) काउंटरों पर

यात्रियों के प्रति प्रतिबद्धता: भारतीय रेल ने दोहराया है कि वह त्योहारों के अवसर पर भी यात्रियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और आरामदायक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

18 साल से ऊपर वालों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, असम सरकार

असम (एजेन्सी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता मिलने से रोकने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को असम में पहली बार आधार कार्ड नहीं मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में 18 वर्ष से अधिक आयु के चाय जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को केवल एक वर्ष तक ही आधार कार्ड मिलता रहेगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को, यदि अभी तक आधार कार्ड नहीं मिला है, तो आवेदन करने के लिए केवल एक महीने का समय दिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के चाय जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगले एक वर्ष तक आधार कार्ड मिलते रहेंगे। सरमा ने कहा कि आधार कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को नागरिकों की पहचान की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है। यह कदम पिछले एक साल में बांग्लादेश से संभावित अवैध आव्रजन से जुड़ी चिंताओं को दूर करने पर सरकार के फोकस को दर्शाता है।

स्वच्छता की दौड़ में दिल्ली बनेगी विजेता: मंत्री रविन्द्र इंद्राज

■ 'दिल्ली को कूड़े से आजादी' अभियान के तहत नरेला में स्वच्छता दौड़ का आयोजन, मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ किया

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने गुरुवार को 'दिल्ली को कूड़े से आजादी' अभियान के तहत नरेला के रामदेव चौक से स्वच्छता दौड़ के आयोजन का हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, स्कूली छात्र-छात्राएं, महिलाएं, युवा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। श्री इंद्राज ने कहा कि दिल्ली को संवारने के लिए स्वच्छता कार्यों को लेकर स्कूलों, कॉलेजों और कॉलोनियों में प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाएं, ये ऐसी प्रतिस्पर्धा होगी जिसमें जीत पूरी दिल्ली की होगी।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प स्वच्छ भारत की दिशा में हो रही इस स्वच्छता दौड़ का उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दिल्ली को कचरे से मुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करना है। विकसित दिल्ली का मूल मंत्र है स्वच्छ दिल्ली। आज की यह स्वच्छता दौड़ केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उस जन आंदोलन का हिस्सा है। इसमें सभी वर्गों की भागीदारी यह दर्शाती है कि दिल्लीवासी मिलकर अपनी राजधानी को स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाएंगे।

श्री इंद्राज ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के निर्देश पर 'दिल्ली को कूड़े से आजादी' अभियान के तहत सभी वार्डों और कॉलोनियों में जन सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत नालियों की सफाई, कचरे का संग्रहण और आधुनिक तकनीक से कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने आग्रह किया कि स्कूलों और कॉलेजों में स्वच्छता क्लब बनाकर छात्रों को इस आंदोलन से जोड़ें। साथ ही नागरिक समितियां और मोहल्ला समितियां अभियान में स्वच्छता प्रहरी बनें और स्थानीय सफाई की निगरानी करें। इन कार्यों को दिल्ली सरकार के स्वच्छता पोर्टल पर अपलोड करें। इससे पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

कार्यक्रम के अंत में स्वच्छता दौड़ में शामिल विजेताओं और योगदान देने वाले अन्य लोगों को प्रमाणपत्र एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के जरिये भी स्वच्छता का सन्देश दिया गया।

हरियाणा के सभी जिलों में संचालित करें उद्यमिता विकास कार्यक्रम: सीएम नायब सिंह सैनी

'प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप अवसरों का पूरा लाभ करें सुनिश्चित'

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने और नए उद्यमियों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में उद्यमिता एवं संकाय विकास कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए। उन्होंने जिलों में उद्यमिता एवं संकाय विकास कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि युवा स्टार्टअप नीति के तहत सृजित किए जा रहे अवसरों का लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री, जो बुधवार देर सांय हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति के अंतर्गत इनक्यूबेटर योजनाओं पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, ने कहा कि उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और अधिक से अधिक युवाओं को नवाचार-संचालित उद्यमों को अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु स्टार्टअप्स को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र में स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी को 60 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने इस लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए प्रयास बढ़ने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि हरियाणा में महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स की वर्तमान हिस्सेदारी 50 प्रतिशत है और जल्द ही इसे बढाकर 60 प्रतिशत किया जायेगा।

यह भी बताया गया कि हरियाणा स्टार्टअप्स के मामले में सातवाँ सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ 9,100 से ज्यादा स्टार्टअप्स DPIIT-पंजीकृत हैं। देश के 117 यूनिकॉर्न में से 19 हरियाणा से हैं, जो राज्य की बढ़ती उद्यमशीलता शक्ति को दशार्ता है। राज्य सरकार ने नए इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना के लिए योजनाओं को स्वीकृति दे दी है, जिसकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। ये केंद्र विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करेंगे।

बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा ने एक जीवंत इनक्यूबेटर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है जो कृषि प्रौद्योगिकी, आईटी, आईओटी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। इनक्यूबेटरस की प्रमुख गतिविधियों में उत्पादों का प्रदर्शन, संभावित उद्यमियों के लिए बूटकैंप का आयोजन, अग्रणी उद्यमियों के साथ नेटवर्किंग, नवोदित निवेशकों के लिए पिचिंग सत्र, सफलता की कहानियाँ प्रस्तुत करना और अनुभवी संस्थापकों और पेशेवरों के साथ परामर्श कार्यक्रम शामिल हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

विमुक्त एवं अर्ध घुमंतु समाज हमारे इतिहास और संस्कृति का गौरवशाली हिस्सा हैं: कपिल मिश्रा

31 अगस्त 1952 को मिली स्वतंत्रता, 'काले कानून' से मुक्त हुआ समाज

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने आज दिल्ली सचिवालय में विमुक्त एवं अर्ध घुमंतु समाज की प्रतिनिधि श्रीमती कविता राठौड़ सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यह बैठक आगामी 31 अगस्त को आयोजित होने वाले विमुक्त एवं अर्ध घुमंतु समाज दिवस की तैयारियों के सिलसिले में हुई।

बैठक में बनजारा, गड़िया, नट, सिख लिगार, मनिहार, लुभाना, गीहरा, सांसी, कलंदर, कालबेलिया, सपेरा और जोगी समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रतिनिधियों ने दिल्ली में घुमंतु विकास बोर्ड की स्थापना तथा जाति प्रमाण पत्र में DNT का उल्लेख किए जाने की मांग रखी। इस अवसर पर श्री कपिल मिश्रा ने कहा-विमुक्त एवं अर्ध घुमंतु समाज हमारे इतिहास और संस्कृति का गौरवशाली हिस्सा रहे हैं। उनकी परंपराएँ, संघर्ष और जीवनशैली भारतीय समाज को विशेष पहचान देती हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि इन समुदायों को उनके अधिकार, सम्मान और अवसर पूरी तरह से मिले।

श्री कपिल मिश्रा ने आगे आश्वासन देते हुए कहा 31 अगस्त को मनाए जाने वाले 'विमुक्त एवं अर्ध घुमंतु समाज दिवस' के लिए दिल्ली सरकार पूरे उत्सव में सक्रिय सहयोग करेगी और भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में समाज के योगदान को प्रदर्शित करने और नई पीढ़ी तक उनकी परंपराओं को पहुँचाने के हर प्रयास में सरकार साथ खड़ी रहेगी।

ब्रिटिश शासनकाल में इन समाजों पर काला कानून थोप दिया गया था, जिसके कारण इन्हें दशकों तक अन्याय और भेदभाव सहना पड़ा। इन समुदायों को अपराधी मानकर उनकी आजादी और गरिमा छीन ली गई थी। लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद 31 अगस्त 1952 को इन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और विमुक्त का दर्जा दिया गया। तभी से यह दिन समाज की गरिमा और पहचान के उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

आगामी 31 अगस्त को दिल्ली में विमुक्त एवं अर्ध घुमंतु समाज दिवस के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, प्रदर्शनी और संगोष्ठियाँ आयोजित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की कला, संस्कृति, वेशभूषा और परंपराओं का प्रदर्शन होगा। यह आयोजन न केवल उनके गौरवशाली इतिहास को याद करेगा बल्कि नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और गर्व का स्त्रोत भी बनेगा।

पंजाब सरकार ने पंचायती जमीनों पर फलदार पौधे लगाने के लिए चलाई विशेष मुहिम

पहले चरण में 9 जिलों की पंचायती जमीन पर 65 एकड़ में लगेंगे फलों के बाग

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने और फसली विविधता लाने के लिए गांवों की पंचायती जमीनों पर फलदार पौधों के बाग लगाएगी। इसी उद्देश्य के तहत आज बागवानी, रक्षा सेवाएं कल्याण एवं स्वतंत्रता संग्रामी मंत्री मोहिंदर भगत और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने संयुक्त रूप से चंडीगढ़ में अपणा पिंड - अपना बाग मुहिम की शुरूआत की। यह मुहिम बागवानी विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के सहयोग से चलाई जा रही है।

अपणा पिंड-अपना बाग मुहिम की शुरूआत करते हुए बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का सपना है पंजाब को रंगला और हरा-भरा बनाना। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से आज इस मुहिम की शुरूआत की गई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत लगाए जाने वाले बागों का रखरखाव पहले 3 साल मगनरेगा द्वारा किया जाएगा। इससे मगनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों को और अधिक रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि 3 साल बाद ये बाग पंचायती संस्थाओं को सौंप दिए जाएंगे। इसके बाद

इन बागों से होने वाली आय संबंधित पंचायत को जाएगी, जो गांवों के विकास पर खर्च होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इन बागों से प्राप्त होने वाले फलों की प्रोसेसिंग से स्वयं सहायता समूहों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।

मंत्री ने बताया कि इस मुहिम के पहले चरण में राज्य के 9 जिलों की पंचायती जमीनों पर 65 एकड़ में बाग लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंधी पहले चरण में जिला गुरदासपुर में 5 एकड़, होशियारपुर में 22 एकड़, जालंधर में 2.5 एकड़, लुधियाना में 5 एकड़, पठानकोट में 15 एकड़, अमृतसर में 2 एकड़, कपूरथला में 4 एकड़, बठिंडा में 6 एकड़ और मलेरकोटला में 4 एकड़ पंचायती जमीन पर बाग लगाए जाएंगे। इस मौके पर बागवानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने एक पुस्तिका भी जारी की। उन्होंने कहा कि पंचायतें प्रस्ताव पारित कर पंचायती जमीनों पर बाग लगाने के लिए सरकार से संपर्क कर सकती हैं।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि पहले राज्य का नहरी पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में जल संसाधन विभाग नहरों के पानी को खेतों की सिंचाई में उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की यह नेक पहल गांवों में बागवानी को प्रोत्साहित करेगी और भूमिगत जल भी बचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह परियोजना ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी सहायक होगी। मंत्री श्री सौंद ने पंचायतों से अपील की कि गांवों की आर्थिक संरचना को और मजबूत करने और क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए पंचायती जमीनों पर फलदार बाग लगाने हेतु सरकार से संपर्क करें।

इस मौके पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत सचिव श्री अजीत बालाजी जोशी, कृषि आयुक्त श्रीमती बबीता, बागवानी निदेशक श्रीमती शैलिंदर कौर, ग्रामीण विकास एवं पंचायत निदेशक श्री उमा शंकर गुप्ता, संयुक्त विकास आयुक्त-कम-आयुक्त मगनरेगा डॉ. शैना अग्रवाल, मुख्य भूमि पाल श्री मोहिंदर सिंह सैनी और अन्य अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।

बाढ़ से प्रभावित हर क्षेत्र का मैं स्वयं पहुँचकर हालात का जायजा ले रहा हूँ: सिंधिया

(एजेन्सी)।

ग्वालियर/भोपाल/ नई दिल्ली। केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को ग्वालियर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संसद का सत्र समाप्त होने के बाद उनका ग्वालियर आगमन हुआ है। वे चार दिन के प्रवास पर गुना, शिवपुरी और अशोकनगर जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ग्रामीण अंचल में बाढ़ से जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और हर जगह लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वे स्वयं प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र तक पहुँच रहा हूँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर कठिन परिस्थिति में आमजन की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास किया है। केंद्र सरकार की पहल पर गृह मंत्री एवं रक्षा

मंत्री से चर्चा कर, एनडीआरएफ की टीम, सेना और हेलिकॉप्टरों को पहले ही तैनात कर दिया गया था। राहत कार्य भी बड़े पैमाने पर संपन्न हो चुके हैं।

सिंधिया ने बताया कि एक दिन का प्रवास उन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ प्रभावित क्षेत्र में किया था और अब तीन दिन का विस्तृत दौरा किया जा रहा है। इसके बाद 24 तारीख को वे दिल्ली लौटेंगे। ग्वालियर के विकास पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में तेज गति से प्रगति हो रही है और योजनाएँ जमीनी स्तर पर साकार हो रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्षा ॠतु समाप्त होने के बाद ग्वालियर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का कार्य भी आरंभ होगा। 130 करोड़ रुपया का निवेश इस परियोजना में किया जाएगा, जिससे स्टेडियम की क्षमता 40,000 दर्शकों तक बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्वालियर और दिल्ली दोनों जगह से वे स्वयं हर कार्य की स्थिति पर पल-पल नजर रख रहे हैं।

सम्पादकीय

उपराष्ट्रपति पद और विचारधारा का चुनाव

मोदी सरकार की किसी भी मामले में मनमानी अब विपक्ष चलने नहीं देगा, इसका एक और उदाहरण सामने आ चुका है। 9 सितम्बर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। गैर राजनैतिक पृष्ठभूमि से आने वाले श्री रेड्डी का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। जो इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उससे पहले दो बार सांसद रह चुके हैं। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष पद को भी संभाल चुके हैं। सी पी राधाकृष्णन के सुदीर्घ राजनैतिक अनुभव और भाजपा के लिए एकनिष्ठता को देखते हुए ही नरेन्द्र मोदी ने उनका नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ाया। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अगले साल होने वाले तमिलनाडु चुनाव में भाजपा सी पी राधाकृष्णन के नाम को भुनाना चाहती है। तमिलनाडु में भाजपा का जनाधार है ही नहीं और एआईएडीएमके के कारण जो थोड़ी बहुत पैठ थी, वो भाषायी विवाद से प्रभावित हो चुकी है। डीएमके की मजबूती भाजपा की तमिलनाडु में उम्मीदों को पूरा नहीं होने दे रही है। ऐसे में तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति बनाकर भाजपा ने बड़ा दांव चलने की तैयारी कर ली थी। भाजपा को यह खुशफहमी थी कि विपक्ष थोड़ी बहुत न नुकुर के बाद सी पी राधाकृष्णन के नाम पर हामी भर देगा। लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं ने विचार विमर्श के बाद मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने श्री सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा की। खरगे ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सर्वसम्मति से सहमति बनी। इंडिया ब्लॉक की बैठक में श्री रेड्डी के नाम पर मुहर लगी थी। इसके साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने एक जरूरी बात कही कि यह विचारधारा की लड़ाई है। संदेश स्पष्ट है कि अब विचारधारा की लड़ाई को किसी भी तरीके विपक्ष छोड़ेगा नहीं, फिर चाहे वह संवैधानिक पद ही क्यों न हो। दरअसल इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी को उतारकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह संविधान, न्यायपालिका और पारदर्शिता के पक्षधर चेहरे को आगे रख रहा है। विपक्ष का मानना है कि श्री रेड्डी की साफ-सुथरी छवि और न्यायिक अनुभव उन्हें उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाता है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद श्री सुदर्शन रेड्डी को गोवा का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने ईमानदार और सख्त छवि वाले अधिकारी के रूप में काम किया। भ्रष्टाचार के मामलों में उन्होंने बिना दबाव के जांच की और पारदर्शिता की पैरवी की। इसलिए उनसे उम्मीद बंधी है कि अगर वे उपराष्ट्रपति बनते हैं तो राज्यसभा को फिर बिना भेदभाव के चलाने का काम करेंगे। जबकि सी पी राधाकृष्णन ने उम्मीदवारी घोषित होने के बाद जो आभार जताया है, उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जे पी नड्डा सबके लिए बार-बार सम्मानित और प्रिय लिख कर बता दिया कि अगर वे उपराष्ट्रपति बनते हैं तो भाजपा की तरफ झुकने से खुद को बचाना उनके लिए कठिन होगा। बहरहाल, देश में अब बिहार चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला होगा। वैसे भारत के संसदीय इतिहास में उपराष्ट्रपति पद के लिए राजनैतिक दांव-पेंच बहुत कम देखने मिले। अमूमन सत्ता और विपक्ष की सहमति से एक ऐसा नाम तय कर लिया जाता था, जिसे संविधान का ज्ञान हो, संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल हो और उपराष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुरूप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो कार्य कर सके। मोदी सरकार के आने के बाद यह परंपरा टूटने लगी। पिछले बार जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाने का चुनाव हुआ था, जिसमें श्री धनखड़ जीत गए थे। लेकिन उनके कार्यकाल में कई किस्म के विवाद खड़े हुए। नौबत तो यहां तक आ गई कि पिछले साल दिसंबर में श्री धनखड़ पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस तक दे दिया था। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, लेकिन इससे यह तो जाहिर हो ही गया कि उपराष्ट्रपति पद पर बैठे जगदीप धनखड़ नीर-क्षीर विवेक की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। उनके कार्यकाल में राज्यसभा में अपवाद स्वरूप ही ऐसे दिन रहे होंगे, जब विपक्ष और उनके बीच बहस न हुई हो। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी सत्रों में और तीसरे कार्यकाल में भी विपक्ष के साथ सभापति के तनाव का सिलसिला तेज हुआ। लेकिन इस बार मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही पहले दिन जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। यह अब तक रहस्य ही है कि जगदीप धनखड़ कहां हैं, किस हाल में हैं, क्या वाकई उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसे कारण बताकर ही उन्होंने पद छोड़ा, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनका इलाज किस अस्पताल में चल रहा है, घर पर चल रहा है तो उसका कोई अपडेट क्यों नहीं है, क्यों इस्तीफे के दिन से अब तक किसी भी भाजपा नेता के साथ न उनका कोई संवाद सामने आया, न मुलाकात की तस्वीरें दिखीं।

जयंती

हरिशंकर परसाई

जन्म-22 अगस्त, 1922, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश; मृत्यु-10 अगस्त, 1995, जबलपुर) हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। ये हिंदी के पहले रचनाकार थे, जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के-फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग्य रचनाएँ हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करतीं, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने-सामने खड़ा करती हैं, जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यमवर्गीय मन की सच्चाइयों को हरिशंकर परसाई ने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन-मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा-शैली में एक खास प्रकार का अपनापन नजर आता है।

पुण्यतिथि

यू. आर. अनंतमूर्ति

जन्म-21 दिसम्बर, 1932; मृत्यु-22 अगस्त, 2014, बैंगलुरू) 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक और शिक्षाविद थे। उन्हें कन्नड़ साहित्य के 'नव्या आंदोलन का प्रणेता' माना जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना 'संस्कार' है। 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' पाने वाले आठ कन्नड़ साहित्यकारों में से वे छठे थे। उन्होंने 'महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय', तिरुअनन्तपुरम और 'केंद्रीय विश्वविद्यालय', गुलबर्गा के कुलपति के रूप में भी काम किया था। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सन 1998 में भारत सरकार द्वारा उन्हें 'पद्म भूषण' से सम्मानित किया गया था। 2013 के 'मैन बुकर पुरस्कार' पाने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची में यू. आर. अनंतमूर्ति को भी चुना गया था।

कल मिलेंगे

पापा-बेटी, बड़ी हो के क्या करोगी?
बेटी-शादी...
पापा-गलत बात है... अभी से किसी का बुरा नहीं सोचते...!

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHI/2016/70240
Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

विधेयक पर हंगामा क्यों, जब मुद्दा है राजनीतिक शुचिता का

आज समय आ गया है कि नए कानून बनाकर राजनीति को अपराधमुक्त बनाने की दिशा में ठोस एवं कारगर कदम उठाए जाएं। यह केवल चुनाव सुधार का मामला नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा को बचाने का प्रश्न है। ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि जिस क्षण कोई जनप्रतिनिधि गंभीर अपराध में आरोपित होकर जेल भेजा जाए या आरोप सिद्ध होने तक हिरासत में रहे, वह स्वचालित रूप से अपने पद से मुक्त हो जाए

-ललित गर्ग

गंभीर आपराधिक आरोपों में घिरे नेता चाहे वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री ही क्यों न हो, उनकी गिरफ्तारी या हिरासत के बाद एक निश्चित अवधि बीत जाने पर हटाने की व्यवस्था वाले विधेयक को जब केन्द्र सरकार ने लोकसभा में प्रस्तुत किया तो जरूरत से ज्यादा हंगामा एवं विरोध समझ में नहीं आया। इस तरह ईमानदार, अपराधमुक्त राजनीति एवं चरित्र सम्पन्न-पवित्र राजनेताओं की पैरवी वाले विधेयक पर हंगामा लोकतंत्र की गरिमा को आहत करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी ओर से इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार भी कर लिया, अब तो विपक्ष को विरोध एवं हंगामें को विराम देते हुए इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसी ईमानदार, समानतापूर्ण एवं आदर्श व्यवस्था क्यों नहीं बननी चाहिए, जिससे उच्च पदों पर बैठे नेताओं के गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी अथवा हिरासत में लिये जाने पर उनके लिये पद छोड़ना आवश्यक हो जाये? आखिर इस आदर्श व्यवस्था में समस्या क्या है? क्यों विपक्ष नैतिक एवं आदर्श राजनीतिक व्यवस्था में अवरोधक बनकर अपने नैतिक चरित्र पर प्रश्न खड़े कर रहा है? क्या इस विधेयक का असर सत्तापक्ष के नेताओं पर नहीं होगा?

आजादी के बाद से कतितय राजनीतिक विसंगतियों के चलते राजनीति में अपराधी तत्वों का वर्चस्व बना रहा है। जनता यह अपेक्षा करती है कि जिन्हें वह अपना प्रतिनिधि चुनती है, वे अपराधमुक्त, निष्कलंक, ईमानदार और चरित्रवान हों। परन्तु स्थिति इसके विपरीत दिखती रही है। एक ओर जनप्रतिनिधि अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं, दूसरी ओर वे पद से इस्तीफा देने या सार्वजनिक जीवन से दूर रहने के बजाय सत्ता की कुर्सी से चिपके रहते हैं। यही प्रवृत्ति जनता के विश्वास को तोड़ती है और राजनीति को संदेह के घेरे में डाल देती है। यह प्रश्न अब और गंभीर हो उठा है कि क्या ऐसे व्यक्तियों को शासन और सत्ता के उच्च पदों पर बने रहने का अधिकार होना चाहिए? क्या लोकतंत्र का आधार अपराध और भ्रष्टाचार पर खड़ा किया जा सकता है? निश्चित ही नहीं। जब तक राजनीति से अपराधी तत्वों का निष्कासन नहीं होगा, तब तक न तो सुशासन स्थापित हो सकता है न ही नया भारत, विकसित भारत एवं आदर्श भारत बन सकता है और न ही राजनीति के प्रति जनता का भरोसा लौट सकता है।

आज समय आ गया है कि नए कानून बनाकर राजनीति को अपराधमुक्त बनाने की दिशा में ठोस एवं कारगर कदम उठाए जाएं। यह केवल चुनाव सुधार का मामला नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा को बचाने का प्रश्न है। ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि जिस क्षण कोई जनप्रतिनिधि गंभीर अपराध में आरोपित होकर जेल भेजा जाए या आरोप सिद्ध होने तक हिरासत में रहे, वह स्वचालित रूप से अपने पद से मुक्त हो जाए। इस्तीफे की प्रतीक्षा या राजनीतिक दबाव की आवश्यकता ही न रहे। अनेक नेताओं ने ऐसा आदर्श प्रस्तुत भी किया, लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा आदि अनेक पार्टियों के नेताओं ने जेल से सरकारें चलाने एवं मंत्री पद पर बने रहने के काले अध्याय रचे हैं, इसी के चलते इस नये विधेयक की अपेक्षा सामने आई।

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में स्वच्छ राजनीति केवल आदर्श नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। जब सत्ता और शासन के केंद्र में अपराधी मानसिकता के लोग बैठते हैं, तो वे शासन को अपने स्वार्थ और अपराधों की ढाल बना लेते हैं। इससे न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था खोखली होती है, बल्कि आम जनता का जीवन भी संकट में पड़ता है। भ्रष्टाचार, धनबल, बाहुबल, भाई-भतीजावाद, हिंसा और अनैतिकता का वातावरण उसी समय पनपता है, जब राजनीति अपराधियों के कब्जे में जाती है। ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले नेताओं की मांग आज पहले से अधिक बढ़ गई है। जनता ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करे। राजनीति यदि सेवा और त्याग का माध्यम बनेगी तो ही समाज का कल्याण होगा। जिन नेताओं पर जरा भी संदेह का धुंधलका हो, उन्हें स्वयं स्वेच्छा से पद छोड़ देना चाहिए। यही परंपरा राजनीति को उच्चता और गरिमा प्रदान कर सकती है।

अपराधमुक्त राजनीति केवल नैतिक अपेक्षा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मजबूरी है। जब तक राजनीति में शुचिता और नैतिकता का स्थान नहीं बनेगा, तब तक सुशासन और ईमानदार प्रशासन की कल्पना अधूरी ही रहेगी। नए कानूनों का निर्माण कर अपराधियों के लिए राजनीति के दरवाजे बंद करना समय की सबसे बड़ी मांग है। यह कदम न केवल लोकतंत्र को सुदृढ़ करेगा, बल्कि जनता के भीतर यह विश्वास भी जगाएगा कि राजनीति वास्तव में लोककल्याण के लिए है, न कि अपराधियों की शरणस्थली। यही अपराधमुक्त राजनीति का दर्शन है, जहां सत्ता अपराधियों का आश्रय-स्थल न होकर समाज की नैतिक ऊर्जा का केंद्र बने। यही उसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है कि वह लोकतंत्र को उसकी वास्तविक आत्मा लौटाए और राजनीति को सेवा, शुचिता और ईमानदारी का प्रतीक बनाए।

भारतीय लोकतंत्र में पिछले कुछ वर्षों से राजनीति और अपराध के गठजोड़ को लेकर गहरी चिंता लगातार उठती रही है। जनता बार-बार यह अपेक्षा करती है कि जिन्हें वे संसद और विधानसभा भेजते हैं, वे न केवल ईमानदार और पारदर्शी हों बल्कि उनके चरित्र और आचरण पर कोई दाग न हो। किंतु बार-बार यही देखने को मिलता है कि गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे नेता भी उच्च पदों पर बने रहते हैं और शासन-सत्ता का उपयोग अपने बचाव के लिए करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया नया विधेयक (संविधान का 130वां संशोधन) एक ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है, केन्द्र सरकार इन विधेयकों को भ्रष्टाचार एवं अपराध विरोध बता रही है, जबकि विपक्ष इससे सहमत नहीं। उनकी असहमति अनेक प्रश्नों को खड़ा कर रही है कि आखिर विपक्ष दागियों की वकालत करते हुए वह स्वयं भी दागी क्यों बन रही है? आशंका जताई जा रही है कि यदि यह संशोधन पारित हो गया तो विपक्ष-शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री अस्थिर हो सकते हैं, उनके पद संकट में पड़ सकते हैं। दरअसल यह विरोध केवल विधेयक का नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक सुविधा, अपनी सत्ता बचाने और सुरक्षा का है। प्रश्न यह उठता है कि क्या विपक्ष वास्तव में अपराधमुक्त राजनीति नहीं चाहता? क्या केवल सत्ता में बने रहने के लिए राजनीति को अपराधियों का अड्डा बनाए रखना आवश्यक है?

विपक्ष का तर्क है कि सरकार इस विधेयक का दुरुपयोग कर सकती है, और केवल आरोप लगाकर भी नेताओं को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि लोकतंत्र में जब तक कानून कठोर और स्पष्ट नहीं होगा, तब तक राजनीति से अपराध का सफाया संभव नहीं है। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप गलत सिद्ध होता है तो उसके लिए पुनः प्रतिष्ठा अर्जित करने के रास्ते खुले रहेंगे, परंतु गंभीर आरोपियों को शासन की कुर्सी पर बने रहने देना लोकतंत्र के साथ अन्याय है, उसकी मूल आत्मा को ध्वस्त करना है। ऐसा अरविन्द केजरीवाल ने पहली बार किया और जेल से ही सरकार चलाने का दम भरते रहे।

आज देश विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत का सपना केवल तकनीकी प्रगति या आर्थिक मजबूती से पूरा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए स्वच्छ, ईमानदार और पारदर्शी राजनीति आवश्यक है। राजनीति में अपराधियों की घुसपैठ न केवल लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है बल्कि जनता के विश्वास को भी तोड़ती है। अपराधमुक्त राजनीति न केवल आदर्श है बल्कि सुशासन और विकास की बुनियादी शर्त है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे विधेयक का स्वागत किया जाए, क्योंकि यह राजनीति को शुचिता, नैतिकता और जनहित के मार्ग पर ले जाने का प्रयास है। राजनीति में एक नये सूरज का उदय है। विपक्ष यदि इसका विरोध करता है तो यह सवाल स्वतः उठता है कि क्यों विपक्ष अपराधमुक्त राजनीति का विरोध करके अपराधियों का संरक्षण कर रहा है? क्या उसे अपने ही दागी नेताओं के लिए भय है? लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने के लिए यह विधेयक समय की मांग है। नया भारत तभी विकसित भारत बनेगा जब उसकी राजनीति अपराधियों से मुक्ति होगी। अपराधमुक्त राजनीति से ही सुशासन आएगा, ईमानदार नेतृत्व पनपेगा और जनता के बीच विश्वास की नई रोशनी जगेगी। यही लोकतंत्र की असली जीत होगी।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसदीय प्रणाली का औसत प्रदर्शन शर्म वाली बात है

विपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार को कटघरे में खड़ा करे, सवाल पूछे और जनहित के मुद्दों पर रचनात्मक बहस करे। लेकिन विपक्ष यदि सवाल पूछने की बजाय हंगामा करने को ही हथियार बनाए, तो यह लोकतंत्र के साथ ही देश की विकास यात्रा के साथ अन्याय है। संसद का हर मिनट करदाताओं के करोड़ों रुपये के बराबर होता है। ऐसे में यह समय और धन व्यर्थ करना देश की प्रगति में बाधा डालने जैसा है

-नीरज कुमार दुबे

भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच संसद जनता के प्रतिनिधियों को नीति और विधायी कार्यों पर गहन विमर्श का अवसर प्रदान करता है। लेकिन आज संपन्न मानसून सत्र इसका विपरीत चित्र प्रस्तुत करता है। हम आपको बता दें कि लगभग एक महीने तक चले इस सत्र में लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 15 विधेयक पारित किए। कागजों पर यह भले उपलब्धि दिखती है, किंतु वास्तविकता यह है कि अधिकांश विधेयक बिना सार्थक चर्चा के शोर-शराबे और हंगामे के बीच पारित हुए।

दोनों सदनों में कामकाज की स्थिति वाकई काफी चिंताजनक रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अनुसार, 419 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे, किंतु बार-बार होने वाले व्यवधानों के कारण मात्र 55 प्रश्नों के ही मौखिक उत्तर हो पाए। साथ ही जहां सत्र की शुरूआत में 120 घंटे चर्चा का लक्ष्य रखा गया था, वहीं विपक्ष के निरंतर गतिरोध के चलते सदन केवल 37 घंटे ही चर्चा कर सका। इसी तरह राज्यसभा का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। उपसभापति हरिवंश के अनुसार, सदन का कुल कामकाज मात्र 38.88 प्रतिशत ही हुआ और शून्यकाल तथा प्रश्नकाल एक बार भी सामान्य तरीके से संचालित नहीं हो सका। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि संसदीय प्रणाली अपनी गुणवत्ता और प्रभावशीलता खोती जा रही है। हम आपको याद दिला दें कि सत्र की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर की थी कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। बावजूद इसके, विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर हंगामा करते हुए लगातार कार्यवाही ठप रखी। परिणामस्वरूप कई सांसद, जो अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को उठाने की तैयारी के साथ संसद पहुँचे थे, अपनी बात रखने से वंचित रह गए। यह न केवल सांसदों की भूमिका को कमतर करता है बल्कि जनता की आकांक्षाओं को भी ठेस पहुँचाता है।

देखा जाये तो संसद का मूल उद्देश्य है-कानून निर्माण पर व्यापक चर्चा और विमर्श। चर्चा से कानून के पक्ष-विपक्ष, उसके प्रभाव और संभावित खामियों पर प्रकाश पड़ता है। किंतु हंगामे के बीच जब विधेयक संक्षिप्त औपचारिकता के बाद पारित होते हैं, तो उनकी गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों प्रभावित होती हैं। यह न केवल विधायी प्रक्रिया की गंभीरता को कम करता है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को भी आहत करता है। इसके अलावा, जिस तरह अन्य क्षेत्रों में नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू है, उसी तरह सांसदों पर भी यह नियम लागू होना चाहिए। यदि वह जानबूझकर हंगामे और व्यवधान के कारण संसद का काम ठप करते हैं, तो करदाताओं के पैसों से मिलने वाले वेतन और भत्तों पर उनका कोई अधिकार नहीं बनता। साथ ही, जिस तरह दागी नेताओं को एक माह तक जेल में रहने पर स्वतः उनका मंत्री पद समाप्त होने के प्रावधान वाला विधेयक पेश किया गया है उसी तरह लगातार हंगामा करने वाले सांसदों की सदस्यता स्वतः समाप्त करने पर भी गंभीर विचार होना चाहिए। यह लोकतंत्र को बचाने और संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

इसके अलावा, यह भी दिलचस्प रहा कि सत्र से पहले यह अपेक्षा थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के पद से हटाने की प्रक्रिया प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनेगी। किंतु अप्रत्याशित रूप से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने इस मानसून सत्र को एक ऐतिहासिक राजनीतिक मोड़ दे दिया।

इसके अलावा, भारत ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है और पूरा राष्ट्र इस लक्ष्य की दिशा में गति पकड़ चुका है। लेकिन जब संसद में विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर व्यवधान डालते हैं, तो यह सीधे-सीधे विकसित भारत की राह में रोड़ा डालने जैसा है। देखा जाये तो विकास की गति केवल सड़कों, पुलों और उद्योगों से नहीं तय होती, बल्कि सुचारु और प्रभावी विधायी व्यवस्था से भी होती है। संसद ही वह स्थान है जहां नीतियों का खाका तैयार होता है, संसाधनों का प्रबंधन तय होता है और जनता की आवाज नीतियों में रूपांतरित होती है। यदि यही मंच बार-बार शोर-शराबे में जकड़ जाए और कार्यवाही बाधित हो, तो विकास की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी?

विपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार को कटघरे में खड़ा करे, सवाल पूछे और जनहित के मुद्दों पर रचनात्मक बहस करे। लेकिन विपक्ष यदि सवाल पूछने की बजाय हंगामा करने को ही हथियार बनाए, तो यह लोकतंत्र के साथ ही देश की विकास यात्रा के साथ अन्याय है। संसद का हर मिनट करदाताओं के करोड़ों रुपये के बराबर होता है। ऐसे में यह समय और धन व्यर्थ करना देश की प्रगति में बाधा डालने जैसा है। आज जब पूरा भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब विपक्षी सांसदों को चाहिए कि वह हंगामा छोड़कर सार्थक बहस और ठोस सुझावों के माध्यम से योगदान करें।

विकास केवल सरकार का नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र और समाज का साझा दायित्व है। यदि संसद ही ठप कर दी जाएगी, तो विकसित भारत का संकल्प केवल एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा। बहरहाल, स्पष्ट है कि भारतीय संसदीय प्रणाली इस समय गंभीर संकट से गुजर रही है। आंकड़े बताते हैं कि संसद का अधिकांश समय सार्थक चर्चा और विधायी कार्यों की बजाय शोर-शराबे में नष्ट हो रहा है। विपक्ष यदि लोकतंत्र की रक्षा का दावा करता है, तो उसे पहले संसद की कार्यप्रणाली को ठप करने की बजाय संवाद और बहस के रास्ते पर लौटना होगा। लोकतंत्र बहुमत और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी से चलता है। संसद को हंगामे की भेंट चढ़ाना देश और जनता के हितों को सीधा नुकसान पहुँचाता है। इसलिए अब समय आ गया है कि संसद में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कठोर नियम बनाए जाएं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं लेकिन यदि हमारी संसदीय प्रणाली औसत दर्जे का प्रदर्शन करेगी तो यह स्थिति हर भारतीय के लिए शर्मनाक है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

भारत ने रोक डाला अमेरिका का माल, पंगा लेना ट्रंप को पड़ रहा भारी

(एजेन्सी)।

कभी कभी कुछ फैसले जो किसान के खेत में लिए जाते हैं वो पूरी राजनीति को बदल कर रख देते हैं। आज बात सिर्फ एक बीज की नहीं बल्कि ये लड़ाई आत्मनिर्भरता बनाम विदेशी दबाव की बन गई है। जिसकी आशंका थी आखिरकार वही हुआ। अमेरिका और भारत की ट्रेड बातचीत फाइनल राउंड में थी। लेकिन अचानक रुक गई और वजह अमेरिकी सोयाबीन है। दरअसल, भारत और अमेरिका के बीच अबतक पांच राउंड की ट्रेड मीटिंग हो चुकी थी। छठा राउंड अगस्त के आखिर में होना था। लेकिन अचानक खबर आई कि यूएस ट्रेड टॉक होल्ड पर चली गई है। अमेरिकी टीम जो 25 अगस्त को भारत आने वाली थी। उसने अपना दौरा रद्द कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अंतरिम ट्रेड डील फाइनल होने वाली थी। लेकिन अब वो अटक गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य वजह भारत का अमेरिकी सोयाबीन को एंट्री न देना है। आपको बता दें कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है। लाखों अमेरिकी सोयाबीन उगाते हैं और वहां की बड़ी कंपनियों में इसे बेचते हैं। इन सबको नए नए बाजार चाहिए। ताकी उनका बिजनेस चलता रहे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फूड ऑयल और प्रोटीन मार्केट है। यहां पर डालों और तेल की भारी खपत होती है। पॉल्ट्री और डेयरी सेक्टर के लिए प्रोटीन विट की भारी डिमांड रहती है। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने दरवाजे खोले और अमेरिकी सोयाबीन यहां टैक्स फ्री आएं। लेकिन भारत ने नो एंट्री फॉर यूएस सोयाबीन साफ कह दिया। दरअसल, भारत के किसानों का सबसे बड़ा फसल आधार सोयाबीन है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कई राज्यों में लाखों किसान सोयाबीन उगाते हैं। अगर अमेरिका का सस्ता सोयाबीन भारत आ गया तो भारतीय किसानों की फसल बिकना मुश्किल हो जाएगी। प्राइस क्रैश हो जाएगा और छोटे किसानों की हालात खराब हो जाएगी। यही वजह है कि भारत ने चार रेड लाइन सोयाबीन, कॉर्न, एथनॉल, डेयरी के रूप में खीची थी।

अमेरिकी सोयाबीन निर्यात परिषद के सीईओ जिम सटर ने बीते दिनों इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा था कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक मुद्दे सुलझ सकते हैं, जिससे भारतीय पोल्ट्री उद्योग को 'स्थायी रूप से सत्यापित' अमेरिकी सोयाबीन फीड उत्पादों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जबकि अमेरिका को चीन के साथ व्यापार तनाव से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान की आंशिक रूप से भरपाई करने की अनुमति मिलेगी।

दबंग दिल्ली ने फिर आशु मलिक पर जताया भरोसा

(एजेन्सी)।

प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन के लिए दबंग दिल्ली केसी ने आशु मलिक को अपना कप्तान बरकरार रखने का फैसला किया है। मैट पर 22 साल के आशु मलिक के प्रदर्शन में निरंतरता, परिपक्वता और जुझारुपन को देखते हुए ही दबंग दिल्ली ने एक बार फिर से बतौर कप्तान उन पर भरोसा जताया है। बता दें कि, आशु ने पिछले साल बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। बतौर खिलाड़ी और कप्तान दबंग दिल्ली के लिए वह बेहद अहम साबित हुए थे।

दबंग दिल्ली केसी के सीईओ प्रशांत मिश्रा ने बताया कि ये सीजन हमारे लिए अहम है। हम लगातार 6 प्लेऑफ प्रदर्शनों से आगे बढ़ते हुए बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए न केवल हमारे खिलाड़ियों के प्रयास की आवश्यकता है, बल्कि मैदान पर मजबूत नेतृत्व की भी आवश्यकता है। आशु इस भूमिका में पूरी तरह से ढल गए हैं। उन्होंने लचीलापन, परिपक्वता और टीम को प्रेरित करने की क्षमता दिखाई है। उनके नेतृत्व में हमें ट्रॉफी जीतने का पूरा भरोसा है। टीम के कोच जोगिंदर नरवाल ने कहा कि आशु लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे हैं। मुझे भरोसा है कि इस साल फिर से टीम का मार्गदर्शन करेंगे। हमारा लक्ष्य प्लेऑफ से आगे बढ़ते हुए खिताब के लिए संघर्ष करना है। पीकेएल 8 की विजेता दबंग दिल्ली आशु मलिक की कप्तानी में नए दृढ़ संकल्प और महत्वाकांक्षा के साथ पीकेएल 12 में कदम रखने के लिए तैयार है। लगातार 6 प्लेऑफ खेलने वाली दबंग दिल्ली का सफर पिछले सीजन सेमीफाइनल में हार के साथ समाप्त हो गया था।

एशिया कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम का ऐलान

(एजेन्सी)।

गुरुवार को हॉकी इंडिया ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की 20 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। ये टूनार्मेंट 5 सितंबर से 14 सितंबर के बीच चीन के हांगझोऊ में होगा। वहीं टीम की कमान सलीमा टेटे के कंधों पर होगा। ये टूनार्मेंट बेहद अहम है क्योंकि जो भी टीम विजेता होगी वह 2026 एफआईएच महिला हॉकी वर्ल्ड कप में सीधी जगह बनाएगी।

वहीं महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरूआत 5 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ करेगी और फिर 6 सितंबर को जापान से भिड़ेगी। भारत अपना अंतिम पूल मैच आठ सितंबर को सिंगापुर के खिलाफ खेलेगा। भारत को पूल बी में रखा गया है।

सलीमा टेटे पिछले साल कप्तान बनने के बाद से टीम की मजबूत कड़ी रही हैं। मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि टीम में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन संतुलन है। उन्होंने बताया कि, हमारा लक्ष्य आक्रामक और अनुशासित हॉकी खेलना है। ये टीम एशिया की शीर्ष टीमों को कड़ी टक्कर देने में सक्षम है। सलीमा ने नेतृत्व में मिडफील्ड को और मजबूती मिलेगी, जिसमें उनके साथ नेहा, लालरेमसियामी, शर्मिला देवी, सुनेलिटा टोप्पो और वैष्णवी विट्ठल फाल्के जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।

महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम

गोलकीपर-बंसारी सोलंकी, बिचु देवी खारीबाम

डिफेंडर-मनीषा चौहान, उदिता, ज्योति, सुमन देवी थोडम, निक्की प्रधान

मिडफील्डर-नेहा, वैष्णवी विट्ठल फाल्के, सलीमा टेटे, शर्मिला देवी, लालरेमसियामी, सुनेलिटा टोप्पो

फोरवर्ड-नवनीत कौर, रुतजा दादासो पिसल, ब्यूटी डुंगडुंग, मुमता खान, दीपिका और संगीता कुमारी

5 सितंबर-भारत बनाम थाईलैंड - भारतीय समयानुसार दोपहर 12:00 बजे

6 सितंबर-जापान बनाम भारत - भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे

8 सितंबर-भारत बनाम सिंगापुर- भारतीय समयानुसार दोपहर 12:00 बजे

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतें साल के अंत तक 3,600 डॉलर तक पहुंचने की आशंका: वेंचुरा

(एजेन्सी)।

वैश्विक आर्थिक प्रतिकूलताओं, भू-राजनीतिक जोखिमों और मजबूत निवेश मांग से दिसंबर के अंत तक वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतें 3,600 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं। वेंचुरा सिक्योरिटीज ने यह बात कही। वेंचुरा सिक्योरिटीज ने अपने नवीनतम अनुमान में कहा कि कॉमेक्स सोना वायदा वर्ष के अंत तक 3,600 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस तक पहुंच जाएगा, जो सात अगस्त को 3,534.10 अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

घरेलू मोर्चे पर अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने के अनुबंधों का वायदा भाव आठ अगस्त को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 1,02,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ने कहा, अमेरिका की कमजोर वृद्धि, अमेरिकी डॉलर सूचकांक पर निरंतर दबाव, व्यापार तनाव और बढ़े हुए भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण सोने में स्पष्ट अस्थिरता के साथ ऊपर की ओर बढ़ने का अनुमान है। वैश्विक मांग के रुझान इस तेजी को और मजबूत कर रहे हैं। 2025 की दूसरी तिमाही में सोने की मांग सालाना आधार पर तीन प्रतिशत बढ़कर 1,249 टन हो गई। इसका मूल्य 132 अरब अमेरिकी डॉलर था जो मूल्य के लिहाज से 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) के माध्यम से निवेश प्रवाह विशेष रूप से मजबूत रहा है, 30 जून तक वैश्विक गोल्ड ईटीएफ होल्डिंग 16 प्रतिशत बढ़कर 3,616 टन हो गईं।

कंपनी ने कहा कि उनकी प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) सालाना आधार पर 64 प्रतिशत बढ़कर 383 अरब अमेरिकी डॉलर हो गईं। इस बीच, भारत में भी वैश्विक रुझान देखने को मिला। घरेलू गोल्ड ईटीएफ में 30 जून तक के वर्ष में होल्डिंग 42 प्रतिशत बढ़कर 66.68 टन हो गई, जबकि एयूएम लगभग दोगुना होकर 64,777 करोड़ रुपये हो गया। गोल्ड ईटीएफ में निवेशक खाते 41 प्रतिशत बढ़कर 76.54 लाख हो गए, जो पिछले चार वर्ष में 317 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा-जोड़ियों का रियलिटी चेक' में नजर आ रही हैं स्वरा भास्कर

(एजेन्सी)। अभिनेत्री स्वरा भास्कर एक बार फिर अपने विचारों को लेकर सुर्खियों में हैं। लगभग हर विषय पर अपनी राय रखने वाली रांझणा स्टार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे सभी लोग मूलतः उभयलिंगी होते हैं। स्वरा भास्कर इन दिनों अपने पति और राजनेता फहाद अहमद के साथ चल रहे रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा-जोड़ियों का रियलिटी चेक' में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री स्वरा भास्कर राजनीतिक और गैर-राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं। फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी और बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाली यह अभिनेत्री एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज के कारण चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने अपने पति फहाद अहमद की मौजूदगी में अपनी कामुकता के बारे में खुलकर बात की और कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर क्रश है। इंडियन एक्सप्रेस स्क्रीन को दिए एक इंटरव्यू में स्वरा ने कहा, 'हम सभी बाइसेक्सुअल हैं। अगर आप लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें, तो वे स्वाभाविक रूप से बाइसेक्सुअल हैं। विषमलैंगिकता सिर्फ. एक मान्यता है, जो हजारों सालों से सांस्कृतिक रूप से मानवता में समाई हुई है।'

श्री खाटू श्याम मंदिर में धूमधाम से मनाई गई भगवान श्री कृष्ण की छठी

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। शहर की पुरानी अनाज मंडी स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में मंगलवार को भगवान श्री कृष्ण की छठी का पर्व बड़े श्रद्धा भाव और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर को रंग-बिरंगे गुब्बारों और पुष्पों से भव्य रूप से सजाया गया। लड्डू गोपाल का अलौकिक श्रृंगार कर पंचामृत स्नान कराया गया। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। मंत्रोच्चारण और विधि-विधान के साथ लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करवाया गया और भगवान के बाल स्वरूप का आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु उत्साहित दिखाई दिए।

छठी के इस पर्व पर करनाल ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों ने पूजा-अर्चना कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा और हर तरफ जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। छठी पर्व के अवसर पर मंदिर कमेटी की ओर से भंडारे का आयोजन भी किया गया जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर अपने आपको धन्य महसूस किया।

मंदिर के मुख्य सेवक देसराज गुप्ता ने बताया कि हर पर्व पर दूर-दराज से भक्तजन यहां पहुंचते हैं। एकादशी के अवसर पर विशेष भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाता है।

श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए मंदिर कमेटी की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। इस अवसर पर देसराज गुप्ता के साथ राजेश गर्ग, महेंद्र गुप्ता, अनिल गर्ग, रामकरण गोयल, विनोद गोयल, आकाश, अशोक सिंघला, पवन गुप्ता, राजेश सिंघला, हरीश सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

जन सुराज कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित

■ बूथ सशक्तिकरण और जनसम्पर्क अभियान पर हुई चर्चा

एसबी ब्यूरो प्रमुख/मृगांक शेखर सिंह

जमुई/गिद्धौर। गिद्धौर स्थित डॉ एन डी मिश्र के आवास स्थान पर बुधवार की देर संध्या जन सुराज पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की बैठक जिलाध्यक्ष उत्तम सिंह के अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान बूथ सशक्तिकरण की समीक्षा की गई।

बैठक की अगुवाई कर रहे नेत्र चिकित्सक डॉ। एन डी मिश्र ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कहा कि बूथ सशक्त होगा तो संगठन अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेगा। बैठक के दौरान आगामी कार्ययोजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया और बूथवार जिम्मेदारियां तय की गयी। सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने संगठन के प्रति निष्ठा व समर्पण के साथ कार्य करने को लेकर संकल्प भी लिया।

इधर डॉ। एन डी मिश्र ने बताया कि आगामी, 02 सितंबर को जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का आगमन जमुई में संभावित है, वो एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इसे लेकर झाझा विधानसभा अंतर्गत गिद्धौर, लक्ष्मीपुर व झाझा प्रखंड के विभिन्न गांव पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं को बूथ की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। डॉ। एन डी मिश्र व जन सुराज के जिलाध्यक्ष उत्तम सिंह ने लोगों से प्रशांत किशोर के संबोधन को सुनने के लिए आमंत्रित किया है।

विदित हो, आगामी चुनाव को लेकर जन सुराज के ओर से बिहार झारखंड के नेत्र चिकित्सक डॉ। एन डी मिश्र झाझा विधानसभा प्रत्याशी के रूप में मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें अपार जन समर्थन भी मिल रहा है।

बैठक में प्रखंड अध्यक्ष काजू सिंह, कार्यकता सच्चिदानंद मिश्र, कुंदन सिंह, अरुण यादव, अजय पण्डित, राकेश कुमार, रूपलाल टुडू, अनुज कुमार, राजेश पंडित, जयप्रकाश झा, राजकुमार यादव, नरेश पासवान, निवास सिंह सहित जन सुराज से जुड़े सैंकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे।

मूलभूत सुविधाओं पर त्वरित कार्रवाई करें अधिकारी: निगमायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने गुरुवार को समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों को वाटर सप्लाई, सीवरेज क्लीनिंग, सेनिटेशन व प्रॉपर्टी आईडी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर किसी प्रकार की समस्या न हो।

निगमायुक्त ने कहा कि सीएम विंडो, समाधान शिविर, जन संवाद, सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर (एसएमजीटी) व सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर आई मांगों व शिकायतों पर अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने सम्बंधित शाखाओं को साप्ताहिक लक्ष्य दिए और कहा कि लक्ष्य पूरे कर रिपोर्ट समय पर सौंपी जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि सीवरेज क्लीनिंग व वाटर सप्लाई की शिकायत दर्ज कराने के लिए नागरिक नगर निगम के टोल फ्री नंबर 14420 पर कॉल कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दो शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

निगमायुक्त ने कार्यकारी अभियंताओं को निर्देश दिए कि किसी भी मांग या शिकायत पर कार्य शुरू करने से पहले उसकी फिजिबिलिटी (व्यवहार्यता) अवश्य जांची जाए। यदि फिजिबिलिटी नहीं है, तो उसे पोर्टल पर दर्ज किया जाए। साथ ही एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) समय पर अपलोड की जाए और कोई भी शिकायत ऑवरड्यू न रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यालय द्वारा पोर्टल पर आई शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाती है, इसलिए सभी अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। उन्होंने उप निगम आयुक्त अभय सिंह को निर्देश दिए कि एटीआर के बावजूद जो शिकायतें दोबारा पोर्टल पर लौट रही हैं, उनकी विशेष समीक्षा की जाए। बैठक में अतिरिक्त निगम आयुक्त अशोक कुमार, मुख्य नगर योजनाकार धर्मपाल सिंह, कार्यकारी अभियंता प्रदीप कल्याण व ओ.पी. करदम, सहायक नगर योजनाकार नवरत्न, अधीक्षक संतोष रानी, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अंकुश पराशर, मुख्य सफाई निरीक्षक सुरेन्द्र चोपड़ा, नायब तहसीलदार राम कुमार तथा ग्रीवेंस सेल के सलाहकार जशनजीत सिंह मौजूद रहे।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो सहनशीलता; 60,000 रुपये की रिश्वत लेते क्लर्क को विजीलेंस ब्यूरो ने रंगे हाथों काबू किया

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा/चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी जीरो सहनशीलता नीति को और मजबूत करते हुए, पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने जिला विकास और पंचायत कार्यालय (डीडीपीओ) फिरोजपुर में तैनात क्लर्क बलवंत सिंह को 60,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। राज्य विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने खुलासा किया कि उक्त आरोपी को फिरोजपुर जिले की तहसील तलवंडी भाई के गाँव लल्ले के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता ने विजीलेंस ब्यूरो से संपर्क कर आरोप लगाया था कि उसने एक निजी बैंक से कृषि ऋण की लिमट बनाने के लिए आवेदन दिया था, जिसमें उसने अपनी स्वामित्व वाली जमीन के क्षेत्र का उल्लेख किया था पर बैंक ने ऋण लिमट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इस मामले के इस संबंध में किसी ने डीडीपीओ कार्यालय को सूचित कर दिया कि शिकायतकर्ता ने अपनी अर्जी में पंचायत जमीन के क्षेत्र का भी उल्लेख किया है जिसे वह नीलामी के बाद खेती कर रहा है।

कचहरी में दो फर्जी अधिवक्ता धड़ाये, किया पुलिस के हवाले

एसबी संवाददाता

वाराणसी। गुरुवार को अधिवक्ता जांच समिति द्वारा फर्जी अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन और सीओपी की जांच दीवानी न्यायालय से लगायत कलेक्ट्रेट में की गई, जांच दल द्वारा इस दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया जांच में दो व्यक्ति ऐसे मिले जो काला कोर्ट, सफेद शर्ट और काला पैंट पहने हुए थे दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़कर उड़ाका दल द्वारा बनारस बार के अध्यक्षीय कक्ष में लाया गया जब जांच समिति ने कड़ाई से पूछताछ किया तो दोनों फर्जी अधिवक्ता निकले उन दोनों के पास न तो बार कौंसिल का पंजीकरण सर्टिफिकेट था और न ही सीओपी बनारस बार के महामंत्री शशांक श्रीवास्तव ने कचहरी चौकी प्रभारी को बुलाकर दोनों को पुलिस के हवाले कर दियोदेर शाम बनारस बार के महामंत्री शशांक श्रीवास्तव ने विवेक कुमार गुप्ता और एस पटेल के खिलाफ कचहरी चौकी प्रभारी को तहरीर दिया गया है, पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई जारी थी।

जांच दल का नेतृत्व बनारस बार के महामंत्री शशांक श्रीवास्तव कर रहे थे उनके साथ जांच में ओम शंकर श्रीवास्तव, दीवाकर दूबे, अमित उपाध्याय, गौतम सिंह, यामिनी शर्मा, रंजीत मिश्रा, कमलेश यादव, विशाल मौर्या, गौतम कुमार झा आदि अधिवक्ता आदि उड़ाका दल के अधिवक्ता शामिल थे।

कथित अधिवक्ता एस के पटेल को पकड़कर ले जाती हुई पुलिस। (छाया: एसबी)

कथित अधिवक्ता विवेक कुमार गुप्ता को कचहरी से पकड़कर ले जाती हुई पुलिस। (छाया: एसबी)

पत्रकार अभिषेक भारती काफी मिलनसार व संघ के प्रति वफादार सिपाही थे-डॉ. धीरज

एसबी ब्यूरो

बेगूसराय। जिले के एलेक्सिया अस्पताल के प्रांगण में अवस्थित महर्षि शांडिल्य वंशज के जिला कार्यालय सभागार में पत्रकार सह महर्षि शांडिल्य वंशज के जिला सचिव अभिषेक भारती के असामयिक निधन हो जाने के उपरांत शोक सभा का आयोजन संघ के संरक्षक पूर्व मुखिया मणिकांत भूषण की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर संघ के संरक्षक पूर्व मुखिया मणिकांत भूषण ने कहा कि संघ के एक होनहार युवक आज हमारे बीच नहीं है। संघ के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान कभी भुलाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मृतक अभिषेक के परिवार वालों के साथ संघ हमेशा साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि संघ का मूल उद्देश्य ही है कि अपने समाज के पिछड़े हुए व्यक्तियों का सहयोग करना।

वहीं एलेक्सिया अस्पताल के निदेशक डॉ. धीरज शांडिल्य ने कहा कि अभिषेक जी काफी मिलनसार व संघ के प्रति वफादार सिपाही थे। संघ के निर्णय के साथ मैं साथ रहूंगा। वहीं उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि अभिषेक के चले जाने से संघ की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। उनकी भरपाई कर पाना मुश्किल है।

इस दौरान उपस्थित सभी लोगों का आंखें नम हो गई। कार्यक्रम के अंत में उनके आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन धारण कर सभा का समापन किया गया। ऊक्त मौके पर व्यास नंदन सिंह, अर्जुन राय, मुकेश सिंह, पप्पू कुमार, ब्रजेश कुमार, मृत्युंजय कुमार, श्रीनिवास सिंह, अमरेश राय, सुजीत कुमार, ज्ञान भारती, हरिशंकर चौधरी, राकेश कुमार, अरुण कुमार सिंह, शिवाकांत सिंह, राजीब चौधरी, अशोक राय सहित दर्जनों शांडिल्य परिवार के लोग मौजूद थे।

सघन एड्स जागरूकता अभियान हेतु गोष्ठी का आयोजन

एसबी ब्यूरो प्रमुख/इंतजार हुसैन

बदायूं। नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज बदायूं में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2025 के उपलक्ष्य में सघन एड्स जागरूकता अभियान के सफल संचालन हेतु एक गोष्ठी का आयोजन डॉ अनीता जैन प्राचार्य की अध्यक्षता में किया गया। इसके बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी (एड्स) डॉ विनेश कुमार द्वारा जनपद में एच आई वी/ एड्स होने के 4 कारण असुरक्षित यौन सम्बन्ध, एच आई वी ग्रस्त महिला से होने वाले उसके बच्चे, एच आई वी ग्रस्त व्यक्ति का ब्लड दूसरे को चढ़ाने, एच आई वी से संक्रमित व्यक्ति की सिरिंज से दूसरे को इंजेक्शन लगाने से फैलता है। शनि दुवे प्रोग्राम मैनेजर लोक कल्याण समिति बदायूं द्वारा बताया गया कि जहाँ एच आई वी के केस निकले हैं। उन ग्राम पंचायतों के साथ साथ एफ एस डब्लू, एम एस डब्लू, ड्रग यूजर्स में एड्स को फैलने, जाँच, बचाव एवं इलाज के बारे में जागरूक किया। सुदेश सक्सेना डीपीटीसी/एसटीएस द्वारा बताया गया की एच आई वी/एड्स से ग्रसित मरीजों में टी बी की बीमारी होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है इसलिए सभी एच आई वी बाले मरीजों की टी बी की जाँच होना आवश्यक है। रेशमबती काउंसलर के द्वारा गर्वभती महिलाओं में एच आई वी की जाँच एवं उसके होने बाले बच्चे को एच आई वी से बचाव के बारे में बताया। राजेश काउंसलर द्वारा भी कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम का संचालन सुदेश सक्सेना द्वारा गया।

कार्यक्रम में डॉ प्रज्ञा पाण्डेय, हिना शहरोंज, राबिया शाकिब, शबा खानम, रुपाली, गीता, साजिया खान, समरीन, शगुफ्ता, शिवांगी वर्मा, महनाज महापरा, फरजाना, शहनाज बानो उपस्थित रहे।

बदायूं चेयरमैन फातमा रजा ने पालिका सीमा से बाहर खेड़ा नवादा पर विशेष सफाई अभियान चलाया

■ विशेष सफाई अभियान में जेसीबी व ट्रैक्टर-ट्रॉली जुटी, कूड़े का पहाड़ और ढेर किया साफ

एसबी ब्यूरो प्रमुख/इंतजार हुसैन

बदायूं। बरेली-आगरा राजमार्ग पर नगर पालिका सीमा से लगे खेड़ा नवादा इलाके में लंबे समय से जमा गंदगी अब अतीत की बात हो गई है। क्षेत्र में फैले कूड़े के ढेर न केवल बदबू फैला रहे थे, बल्कि बीमारी फैलने का भी खतरा बढ़ा रहे थे। इसकी शिकायत लगातार स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही थी।

इलाके के नागरिक ग्राम पंचायत के प्रधान से लगातार बरेली मार्ग पर खेड़ा नवादा में भीषण गंदगी व कूड़े के लगे ढेर की शिकायते कर रहे, जब कोई सुनवाई नही हुई, कोई राहत नहीं मिली तो नगर पालिका चेयरमैन से गुहार लगाई। पालिका चेयरमैन ने तुरंत एक्शन लेते हुए खेड़ा नवादा में विशेष सफाई अभियान चलाने का आदेश दे दिया।

पालिकाध्यक्ष फातमा रजा के निर्देश पर नगर पालिका ने विशेष सफाई अभियान चलाया। मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक मोहम्मद तय्यव, सफाई खाद्य निरीक्षक केशव गंगवार की देखरेख में सफाई कर्मचारियों की टीम ने ट्रैक्टर-ट्रॉली और जेसीबी लगाकर गंदगी के ढेर हटा दिए। कूड़ा हटने के बाद रास्ता पूरी तरह साफ हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। सफाई अभियान के दौरान स्थानीय लोगों ने पालिका टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कदम काफी समय से अपेक्षित था। नागरिकों ने साथ ही यह उम्मीद जताई कि पालिका भविष्य में भी नियमित रूप से सफाई करवाती रहे, ताकि क्षेत्र में दुबारा गंदगी न पनपे।

शाहनवाज हुसैन का विधायक एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत

एसबी ब्यूरो प्रमुख/मृगांक शेखर सिंह

जमुई/गिद्धौर। गिद्धौर के लालकोठी में भाजपा के वरिष्ठ नेता विधान परिषद के सदस्य सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन का जमुई विधायक श्रेयसी सिंह के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक श्रेयसी सिंह बड़ी बहन मानसी सिंह द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत सम्मान किया गया।

वहीं इस मौके पर दादा वरिष्ठ भाजपा नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दिवंगत देता दिग्विजय सिंह से जुड़ी यादों एवं स्मृतियों को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया साथ ही मौके पर दिवंगत नेता दिग्विजय सिंह के तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं मौके पर कई राजनीतिक विषयों पर विधायक सुश्री श्रेयसी सिंह से वार्ता की।

इस अवसर पर बड़ी बहन श्रीमति मानसी सिंह, केकेएम कॉलेज के पूर्व प्राचार्य सह भाजपा नेता श्री अफजर शम्सी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रकाश भगत, महा मंत्री सोनेलाल पासवान, उपाध्यक्ष विनय पांडेय, गोपाल कृष्ण, कोषाध्यक्ष अजय पासवान, सिकंदरा मंडल अध्यक्ष अखिलेश पांडेय सहित कई पार्टी कार्यकर्ता एवं गणमान्य गणमान्य मौके पर उपस्थित थे।

पूर्व मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन से भेंट कर चर्चा करते विधायक श्रेयसी सिंह मानसी सिंह व अन्य कार्यकर्ता गण। (छाया: एसबी)

जैविक व प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हों किसान: रमाकान्त उपाध्याय

■ गोबर व गोमूत्र बहुमूल्य: गोसेवा आयोग सदस्य

संजना भारती संवाददाता

बदायूँ। उ0प्र0 गोसेवा आयोग के मा0 सदस्य रमाकान्त उपाध्याय ने गौ-संरक्षण व संवर्धन की जिला स्तरीय अनुसंधान मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को गोवंशों की चिंता करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोवंशों के संरक्षण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क पर कोई निराश्रित गोवंश नजर नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोबर व गोमूत्र बहुमूल्य हैं। गाय के मूत्र में बर्बरीन नामक तत्व पाया जाता है जिससे कैंसर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सहभागिता योजना के गौ पालकों को सब्सिडी पर वायोगैस संयंत्र दिया जाए, जिससे वह जैविक व प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर होंगे। उन्होंने कहा कि कुपोषित गोवंशों का विशेष ध्यान रखा जाए तथा गांवंश को दिए जा रहे हैं चारे की गुणवत्ता तथा पीने के पानी की शुद्धता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि गोवंशों के संरक्षण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार गोवंशों के संरक्षण के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सड़क पर कोई निराश्रित गोवंश नजर नहीं आना चाहिए।

उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह जनपद के किसानों को प्राकृतिक व जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अपने कार्यालय में नमामि गंगे, यूपी डास्प, कृषि व उद्यान आदि संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करें। मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने जनपद में गो-संरक्षण की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि जनपद में 294 ग्रामीण क्षेत्र, 03काजीं हाऊस, 05 वृहद गो-संरक्षण, 03 कान्हा गोवंश आश्रय स्थल, 12 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल संचालित है। साथ ही 7833 गोवंश को मा0 मुख्य मंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना अन्तर्गत सुपुर्दगी में दिया गया है। जिसमें 34357 गोवंश संरक्षित किये गये है। जनपद में गोवंश सरक्षण का कार्य लगातार जारी है। मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी डॉ0 समदर्शी सरोज ने बताया कि जनपद में 05 वृहद गो-संरक्षण केन्द्र, एवं 03 कान्हॉ पशु आश्रय स्थल निर्माणाधीन है जिसको जल्द ही संचालित कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 05 कान्हॉ पशु आश्रय स्थल एवं 05 वृहद गो-संरक्षण केन्द्र हेतु भूमि चिन्हॉकन की कार्यवाही की जा रही है। जनपद में गोवंश संरक्षण अन्तिम गोवंश संरक्षित किये जाने तक जारी रहेगा। इससे पूर्व आयोग सदस्य ने गौशालाओं का निरीक्षण कर वहां की गई व्यवस्थाओं लेते हुए अधिकारियों को ठीक से गौवंशों का संरक्षण करने के निर्देश दिए। बैठक उपरान्त उन्होंने मीडिया से वार्ता भी की।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन, समस्त खण्ड विकास अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

विधायक जगमोहन आनंद ने कैंप कार्यालय में सुनी जनता की समस्याएं, मौके पर किया समाधान

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। विधायक जगमोहन आनंद ने वीरवार को सेक्टर-13 स्थित कैंप कार्यालय में आमजन की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को एक-एक करके सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देकर समाधान करवाया।

विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश में नॉन स्टॉप विकास कार्य करवा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार आम जनता की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है।

विधायक ने आमजन से अपील की कि जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आए, वह लिखित शिकायत के साथ पहुंचे। शिकायत पत्र में संबंधित व्यक्ति का पता और मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज हो, ताकि आसानी से संपर्क किया जा सके।

उन्होंने बताया कि आमजन की समस्याओं का प्रतिदिन फॉलोअप लिया जाता है। इस कार्य के लिए उनके आवास पर कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जो विभागों से लगातार जानकारी लेकर समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं।

करनाल नगर निगम की बैठक सफल, 625 गौवंश को गौशालाओं में भेजने पर बनी सहमति

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। नगर निगम कार्यालय में उप निगमायुक्त अभय सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में गौशाला संचालकों व प्रतिनिधियों ने सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि करीब 625 बेसहारा गौवंश को विभिन्न गौशालाओं में स्थानांतरित किया जाएगा।

उप निगमायुक्त अभय सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार 1 अगस्त से 31 अगस्त तक बेसहारा गौवंश पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम करनाल क्षेत्र से अब तक लगभग 185 गौवंश को पकडकर फूसगढ़ स्थित गौशाला व नंदीशाला में भेजा गया है। बैठक में सहमति बनी कि गगसीना गौशाला में 27 गौवंश भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा उपलाना व गोंदर गौशाला में 200-200, अमुपुर में 100, जुण्डला व चोचड़ा में 50-50 तथा पाडा गौशाला में 25 गौवंश भेजे जाएंगे। अभय सिंह ने कहा कि नगर निगम की गौशाला और नंदीशाला क्षमता से अधिक भरी हुई है, इसलिए अन्य गौशालाओं का सहयोग जरूरी है। उन्होंने अपील की कि जिला की सभी गौशालाएं आगे आकर सेवा कार्य में योगदान दें ताकि कोई भी गौवंश बेसहारा न रहे। उप निगमायुक्त ने चेतावनी दी कि जो लोग दूध निकालने या उपयोग खत्म होने के बाद अपने पशुओं को बेसहारा छोड़ देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे पशुओं को जब्त कर लिया जाएगा और मालिक को वापिस नहीं किए जाएंगे। साथ ही संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

चाबा गांव में किया गया रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन

■ एडीसी ने ग्रामीणों से किया सीधा संवाद, मौके पर हुई समस्याओं की सुनवाई

एसबी संवाददाता

गुहला-चीका। हर माह गांव में आयोजित होने वाले रात्रि प्रवास कार्यक्रम के तहत वीरवार को गांव चाबा में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां डीसी प्रीति के मार्गदर्शन में एडीसी दीपक बाबूलाल करवा, सीईओ जिला परिषद सुरेश राविश, एसडीएम कैप्टन प्रमेश व डीएसपी कुलदीप बेनीवाल ने न केवल ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इसके साथ गांव के विकास से जुड़े ग्रामीणों के सुझावों को भी सुने।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने कहा कि रात्रि ठहराव कार्यक्रम का उद्देश्य जनता के द्वार पर पहुंच कर उनकी समस्याओं को जानना तथा उनको दूर करना है। कार्यक्रम के दौरान जो भी समस्याएं आई है उनको समाधान करवाया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जानकारी देते हुए आमजन से सोलर सिस्टम लगवाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सोलर सिस्टम पर अनुदान दिया जा रहा है, बिल्कुल नाम मात्र रुपये में यह सिस्टम लग जाता है। लोगों को बिजली के बिलों में भी बड़ी राहत मिलती है । इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्त रहने के लिए अच्छा खान पान लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों ने घग्गर पार का होने के चलते गांव को लेकर जो समस्याएं रखी हैं, पूरा प्रयास किया जाएगा कि इन समस्याओं का समाधान हो। कार्यक्रम में चाबा सहित आस-पास के गांवों के ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं जैसे खराब सड़कें, चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने, नशे की समस्या के समाधान, स्टेडियम की चारदीवारी, बिजली बिल, पेंशन, जमीन विवाद, गांव में साफ-सफाई संबंधी समस्याएं रखीं। साथ ही गांव में रोडवेज बस सेवा, बैंक ब्रांच खोलने, सीसीटीवी कैमरा लगवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस समस्या का तुरंत समाधान हो सकेगा, उसे करवाया जाएगा। शेष मांगो के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ताकि लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े।

एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि खुले दरबार में जो भी शिकायतें आई हैं, उनका त्वरित समाधान करवाया जाएगा। लोगों से अपील है कि वे नशे के खात्मे में नशा मुक्त हरियाणा अभियान में सहयोग दें। क्षेत्र की सड़क संबंधी शिकायतों पर जल्द संज्ञान लिया जाएगा। इस क्षेत्र की काफी संख्या में सड़कों के टेंडर लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रात्रि प्रवास कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाना है। कार्यक्रम में सीईओ जिला परिषद सुरेश राविश ने कहा कि एडीसी महोदय के निर्देशानुसार गांव में बने स्टेडियम की चारदीवारी करवाने तथा सीसीटीवी कैमरा लगाने जो आवश्यक कार्रवाई होगी, उसे पूरा किया जाएगा। यह सरपंच का सराहनीय फैसला है कि स्टेडियम के लिए एक एकड़ जमीन दी है। उन्होंने कहा कि सरकार व जिला प्रशासन जनता की सेवा लिए सदैव तत्पर है।

इस अवसर पर डीआरओ चंद्रमोहन, डीडीपीओ रितु लाठर, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी नसीब सैनी, रेडक्रॉस सोसायटी सचिव रामजी लाल, एलडीएम एसके नंदा, जिला बागवानी अधिकारी डॉ हीरालाल, सीडीपीओ शशि बाला, नायब तहसीलदार बंसी लाल, बीईओ बलबीर कश्यप, सुरेश कौशिक अधीक्षक, जिला विज्ञान विशेषज्ञ सुशील कुमार डॉ. बीरबल दलाल सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

युवाओं को नशे से दूर करने के लिए समाज को जागरूक करना जरूरी: एसपी आस्था मोदी

जिला कैथल पुलिस की नशा विरूद्ध जागरूकता मुहिम जारी। (छाया: एसबी)

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। जिला पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी के आदेशानुसार कैथल पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ एक विशेष जागरूकता मुहिम चलायी जा रही है। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना तथा आमजन को इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना है। एसपी आस्था मोदी ने कहा कि आज के समय में नशा समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है।

नशे की लत व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर देती है। यह न केवल एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद करती है बल्कि परिवार और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल कानूनन कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को सही मार्गदर्शन देना और जागरूक करना भी उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत नशा जागरूकता टीम में शामिल एसआई कर्मबीर, एएसआई ओमप्रकाश, एचसी सुनील कुमार, महिला सिपाही किस्मत, एसपीओ राजपाल तथा एसपीओ प्रदीप कुमार की टीम लगातार गांव-गांव जाकर आमजन से संवाद कर रही हैं।

विद्यार्थियों, युवाओं और ग्रामीणों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। नशा छोड़ने वाले व्यक्तियों को काउंसलिंग देकर फिर से समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। एसपी ने कहा कि नशे से जूझ रहे व्यक्ति का परिवार और समाज यदि सही सहयोग दे, तो वह व्यक्ति आसानी से नशा छोड़ सकता है। उन्होंने अपील की कि हर व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों पर नजर रखनी चाहिए और यदि कोई नशे की गिरफ्त में है तो उसका सही इलाज और परामर्श करवाना चाहिए। उन्होंने कहा-अपना नहीं तो परिवार का ख्याल करो, नशा छोड़कर सबका कल्याण करो।

एसपी आस्था मोदी ने यह भी कहा कि नशे की लत भी एक बीमारी है, जिसका इलाज संभव है। इच्छाशक्ति और परिवार का साथ, किसी भी नशे के शिकार व्यक्ति को एक नई जिंदगी दे सकता है। पुलिस का यह अभियान तभी सफल होगा जब समाज भी इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा।

डीएलएसए द्वारा पैनल अधिवक्ताओं, पैरा लीगल वालंटियर, लीगल एड डिफेंस काउंसल व स्टाफ के लिए वर्कशॉप आयोजित

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय कुमार शारदा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा पैनल अधिवक्ताओं, पैरा लीगल वालंटियर, लीगल एड डिफेंस काउंसल व स्टाफ के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. इरम हसन ने किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित पैनल अधिवक्ताओं, पैरा लीगल वालंटियर, लीगल एड डिफेंस काउंसल व स्टाफ को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाने संबंधी गठित आंतरिक व स्थाई कमेटियों की जानकारी दी। वर्कशॉप में असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसल बिंदिया ने यौन उत्पीड़न संबंधित अधिनियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रोजेक्टर के जरिए पीपीटी प्रस्तुत कर संबंधित कानूनों से प्रतिभागियों को अवगत करवाया।

इसके अलावा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने यूनाइटेड नेशनल के सदस्यों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यशैली और मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जन साधारण को जागरूकता शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक कानूनी जानकारी दी जाएगी ताकि वे अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ सकें।

डीसी प्रीति ने किया ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

निर्मल कुमार

कैथल। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार लघु सचिवालय स्थित ईवीएम वेयरहाउस में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रीति ने मासिक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान ईवीएम की व्यवस्थाओं लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और फीडबैक लिया। डीसी प्रीति ने निर्वाचन विभाग के अधिकारियों को कहा कि ईवीएम वेयरहाउस की साफ-सफाई व्यवस्था को निरंतर बनाए रखें, कहीं भी कोई भी लापरवाही न बरती जाए। इसके अलावा बिजली, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों तथा आपातकालीन व्यवस्थाओं आदि के बारे में पूर्ण जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ चुनाव नायब तहसीलदार सुभाष चंद व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार, गाड़ी से वर्दी व फर्जी आई कार्ड बरामद

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। चौकी महमुदपुर पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को गुमराह करने वाले एक युवक को काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से पुलिस की वर्दी, फर्जी आई कार्ड सहित अन्य सामान बरामद हुआ है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस चौकी महमुदपुर के हेड कॉन्स्टेबल मंगल सिंह की टीम समानाझचीका रोड पर गश्त कर रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि गांव थेह बनेहड़ा जिला कैथल निवासी विजय कुमार अपने आप को कुरुक्षेत्र पुलिस का साइबर सैल कर्मी बताकर लोगों को गुमराह करता है और आज अपनी कार में सवार होकर पंजाब की ओर जाने वाला है। सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी एसआई बलराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महमुदपुर बस अड्डा के पास नाकाबंदी की। थोड़ी देर बाद जैसे ही एक आल्टो कार मौके पर आई, पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो चालक गाड़ी मोड़कर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर आरोपी को काबू कर लिया। आरोपी उस समय हरियाणा पुलिस की लोगो लगी टी-शर्ट पहने हुए था। पूछताछ में आरोपी की पहचान विजय कुमार निवासी थेह बनेहड़ा के रूप में हुई। उसने झूठा दावा किया कि वह कुरुक्षेत्र साइबर सैल में तैनात है। सत्यापन करने पर पता चला कि ऐसा कोई कर्मचारी पुलिस विभाग में नहीं है। तलाशी के दौरान आरोपी की कार से पुलिस वर्दी, बेल्ट, जूते, कैप, फर्जी पुलिस आई कार्ड, लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल फोन व अन्य सामान बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ थाना गुहला में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी शातिर किस्म का है, जो कई स्थानों पर पुलिसकर्मी बनकर घूमता और लोगों को गुमराह करता रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी पुलिस वाला बनकर कई जगह नाको पर जाकर आमजन से पैसे भी एंठ चुका है। व्यापक पूछताछ के लिए आरोपी का अदालत से 5 दिन पुलिस रिमांड हासिल किया गया है।

फर्जी आरोपी पुलिसकर्मी चौकी महमुदपुर पुलिस गिरफ्त में। (छाया: एसबी)

पीएम जीवन ज्योति तथा पीएम सुरक्षा बीमा योजनाओं को लाभ उठाएं आमजन: डीसी प्रीति

एसबी संवाददाता

कैथल। डीसी प्रीति ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नागरिकों के लिए कारगर सिद्ध हो रही है। इन योजनाओं के फार्म प्रत्येक बैंक व डाकघर में उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में निर्धारित वार्षिक प्रीमियम जमा करवा कर दो लाख रुपए तक का बीमा होता है। सभी नागरिक इन योजनाओं का लाभ उठाएं।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक बैंक उपभोक्ता को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने के लिए दो योजनाएं चलाई हुई हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना सामान्य परिवार को मुश्किल की घड़ी में आर्थिक समर्थन देकर मजबूत बनाती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्ति नामांकन करवा सकते है। योजना के तहत 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना होता है तथा इससे 2 लाख रुपए के जीवन बीमा का संरक्षण मिलता है।

उपायुक्त कैथल प्रीति।

डीसी प्रीति ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के नागरिक अपना दुर्घटना बीमा करवा सकते है। केवल 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा संरक्षण प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि इन बीमा योजनाओं का प्रीमियम उपभोक्ता के बैंक या डाकघर खाते में से ऑटो डेबिट होता है तथा दावे की राशि संबंधित के बैंक खाते में सीधे जमा हो जाती है। इन योजनाओं में नामांकन करवाने के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा अथवा डाकघर से संपर्क करें।

उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

दादी प्रकाशमणि की स्मृति में 23 को होगा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन: बीके सरिता

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असन्ध। संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 18वीं पुण्य स्मृति में 23 अगस्त को करनाल रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। उपरोक्त जानकारी बीके सरिता ने देते हुए बताया कि यह आयोजन दादी प्रकाशमणि के त्याग और सेवा के संदेश को समर्पित है। उन्होंने सभी से इस मानवता के पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। बीके उषा दीदी ने बताया कि राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 18वीं पुण्य स्मृति में पूरे देश में रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे है जिनमें 1 लाख यूनिट रक्तदान का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर में सभी बढ़ चढ़कर भाग ले।

आयुर्वेद को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास: आरती सिंह राव

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव के नेतृत्व में, महेंद्रगढ़ ज़िले के नारनौल के पटिकरा गाँव स्थित बाबा खेतानाथ राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल ने आयुर्वेदिक शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एडं सर्जरी पाठ्यक्रम के लिए सीटों की संख्या पिछले वर्ष के 30 से बढ़कर 63 हो गई है। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग द्वारा इस संबंध में अनुमोदन मिलने के बाद यह उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य आयुर्वेद को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक मजबूत चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करना है। बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक कॉलेज में सीटों की संख्या में वृद्धि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का भविष्य उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा और विश्वसनीय शोध में निहित है।

हम चाहते हैं कि हमारे संस्थान विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त चिकित्सक, शोधकर्ता और शिक्षक तैयार करें जो आयुर्वेद को नई ऊँचाइयों पर ले जा सकें।

बल्ला में चिकित्सा कैंप का किया आयोजन

संजना भारती संवाददाता

असंध। गांव बल्ला दादा खेड़ा के प्रांगण में उप मण्डल नागरिक अस्पताल असंध वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. सूबे सिंह के आदेशानुसार आईसीटीसी असंध द्वारा संगठित चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में गांव बल्ला के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया।

इस मौके पर आईसीटीसी काउंसलर रंगी राम वर्मा ने उपस्थित जनसमूह को एचआईवी/ एड्स, टीबी, काला पीलिया, गुप्त रोग एवं शुगर के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इसके साथ-2 उन्होंने लोगों को नशे की लत से भी दूर रहने के लिए प्रेरित किया व बताया कि सुइयों से नशा लेने के कारण ज्यादातर युवाओं में एचआईवी/एड्स और काला पीलिया की बीमारी फैलने का मुख्य कारण बन गया है जिसने असंध क्षेत्र के भी बहुत सारे युवाओं को लपेट लिया है। हमें नशे से दूर रहना होगा। एचआईवी/ एड्स और टीबी से ग्रस्त लोगों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जा रही है जिसमें एचआईवी/एड्स के मरीजों को 2250 रुपए महीना और टीबी के मरीजों को 1000 रुपए महीना दिया जा रहा है। इस मौके पर आईसीटीसी, लैब टेक्नीशियन प्रीति शर्मा द्वारा 54 व्यक्तियों की एचआईवी/एड्स, काला पीलिया की जांच की गई। एमपीएचडब्ल्यू हरपाल सिंह व ए.एन.एम. गुंजन द्वारा लोगों की शुगर, बीपी व टीबी की जांच की गई। इस मौके पर ममता, बृजबाला, संतोष, अनिता, सुदेश आदि आशा वर्कर भी मौजूद रहीं।